सम्पादक की कलम से

देश के लिए शहीद होने वाले सैन्यकर्मियों के परिवारों पर कितना प्रतिकूल असर पड़ेगा, इसकी किसी नेता को चिंता नहीं है। पुलवामा हमले में शहीद हुए सैन्यकर्मियों के परिवारों के तो अभी आंख के आंसू भी नहीं सूखे हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत-पाक में हुई एयर स्ट्राइक के बाद केंद्र की भाजपा सरकार और विपक्षी दलों में चल रही खींचतान इसकी गवाह है। देश के लोगों ने इस पूरे मसले को जितनी गंभीरता से लिया, राजनीतिक दल उतना ही बचपना दिखा रहे हैं। यह सारी कवायद आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर की जा रही है। सत्तारूढ़ भाजपा इसे भुनाने की दाएं-बाएं से कोशिश कर रही है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने में लगे हुए हैं।

सत्ता पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे से सवाल-जवाब में उलझे हुए हैं। एक भी दल जिम्मेदारी नहीं दिखा रहा है। भाजपा एयर स्ट्राइक का श्रेय लेने में जुटी हुई है, वहीं विपक्षी दल उसकी घेराबंदी करके इसे चुनावी चाल करार देने पर तुले हुए हैं। यहां तक की पाकिस्तानी मीडिया भी सत्ता को लेकर दलों में फैले इस दलदल को सुर्खियां बनाकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने सफाई पेश करने में जुटा हुआ है। इससे पहले भी विधान सभा चुनावों के दौरान सेना की स्ट्राइक पर राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे पर जमकर लांछन लगाए थे। पुलवामा हमले में शहीद हुए सैन्यकर्मियों के परिवारों के तो अभी आंख के आंसू भी नहीं सूखे हैं। सभी दल सेना के पराक्रम पर अपनी-अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगे हुए हैं। एक-दूसरे की छिछालेदार पर उतर आए हैं। राजनीतिक दलों का अब तक चारित्रिक इतिहास इसका गवाह रहा है कि ऐसे संवेदनशील मौकों को भी उन्होंने राजनीतिक तौर पर भुनाने का प्रयास किया है।

इस एयर स्ट्राइक के बाद भी लगने लगा था कि राजनीतिक दल इसे भुनाए बगैर नहीं मानेंगे। उनके इन आरोप-प्रत्यारोपों ने देश में जगे देशभक्ति के जज्बे को कमजोर करने का काम किया है। पुलवामा के शहीदों के बाद पूरा देश शोक में था। पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों पर वायुसेना की कार्रवाई के बाद नागरिकों का सदमा काफी हद तक कम हुआ। लगने लगा कि भारत ऐसी नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने का साहस रखता है। विंग कमांडर अभिनंदन के पाकिस्तान के लड़ाकू विमान एफ-16 को मार गिराए जाने के दौरान पकड़े जाने पर देश में एक बार फिर देशभक्ति के साथ एकता का संचार हुआ। देश भर से अभिनंदन के रिहाई की दुआएं की जाने लगीं। विश्व समुदाय के दबाव के सामने आखिरकार पाकिस्तान को जांबाज विंग कमांडर को रिहा करना पड़ा। देशभक्ति से सरोबार पूरे देश में इसका जश्न मनाया गया। राजनीतिक दल यदि सत्तालोलुपता नहीं दिखाकर इस ज्वार को देश के निर्माण की दिशा में मोड़ने का प्रयास करते तो भारत मजबूती के रास्ते पर कुछ कदम आगे बढ़ता।

इससे देश की एकता-अखण्डता और मजबूत होती। नए राष्ट्रवाद का संचार होता। इसके विपरीत राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे के खिलाफ सवाल-जवाबों का दौर शुरू कर दिया। देश के लोगों की सकारात्मक ताकत को नकारात्मक में बदलने का काम किया गया। उनके जज्बों को सही दिशा में नेतृत्व देने के बजाए राजनीतिक दल आपस में ही उलझ गए। इससे राजनीतिक दलों ने यह साबित कर दिया कि उनके लिए सत्ता ही सर्वोपरि है। देश की एकता-अखंडता को मजबूत करने के प्रयासों को दलों की ऐसी करतूतों से ही झटका लगता है।

FORM-IV
(See Rule 8)

Statement about ownership & other Particulars about Newspaper

1.	Place of Publication	:	INDORE
2.	Periodicity of its Publication	:	MONTHLY
3.	Printer's Name Whether citizen of India? (If foreigner, state the country of origin) Address	: : :	RAVI KUMAR POTDAR Yes 72/74, Suyash Vihar, Indore (M.P.)
4.	Publisher's Name Whether citizen of India? (If foreigner, state the country of origin) Address	: : :	RAVI KUMAR POTDAR Yes 72/74, Suyash Vihar, Indore (M.P.)
5.	Editor's Name Whether Citizen of India? (If foreigner, state the country of origin) Address	: : :	RAVI KUMAR POTDAR Yes 72/74, Suyash Vihar, Indore (M.P.)
6.	Names and Addresses of invividuals who own the Newspapers and partners of share holders holding more than one per cent of the total capital.	:	RAVI KUMAR POTDAR Indore (M.P.) 72/74, Suyash Vihar, Indore (M.P.)

I, RAVI KUMAR POTDAR, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/-

Date : 01.03.2019 Signature of Publisher

अलगाववादियों की सुरक्षा और सुविधाएं छिनना सही दिशा में उठाया गया कदम

संभवत: यह पहला मौका है जब सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद की जड़ काटने का सीधा प्रयास किया है। होता यह रहा है कि आतंकवादी गतिविधियां तेज होने पर जनआक्रोश के चलते अलगाववादी नेताओं को नजरबंद या फिर जेल में बंद कर दिया जाता रहा है। इससे उनकी गतिविधियों पर किसी तरह की रोक भी नहीं लग पाती और वे अधिक क्षमता से अलगाववाद को बढ़ावा देने में सक्रिय हो जाते हैं।

मजे की बात यह कि देश की सुविधाओं का उपयोग करते हुए देश के खिलाफ खुले आम राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का संचालन करते रहे हैं। पहली बार सरकार ने अलगाववादी नेताओं पर सीधा शिकंजा कसने का कदम उठाया है। इससे पहले नजरबंदी या जेल में बंद करने जैसे कदम उठाए जाते रहे हैं जिनका इन पर इसलिए कोई असर नहीं होता था कि इनकी सुख और सुविधाओं में कोई कमी नहीं होती थी और सहानुभूति बटोरते हुए अधिक सक्रियता से अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे।

पांच शीर्ष अलगाववादी नेताओं मीरवाइज उमर फारुख, अब्दुल गनी बट, बिलाल लोन, शब्बीर शाह और हाशिम कुरैशी पर सख्ती करते हुए सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही सुरक्षा और अन्य सुविधाओं को हटा दिया गया है। एक आरटीआई सूचना के अनुसार इन अलगाववादी नेताओं पर देश के खजाने से 10 करोड़ रुपए से अधिक तो सुरक्षा के नाम पर ही सालाना खर्च किए जा रहे थे। इसके अलावा होटलों का खर्चा, मंहगे ईलाज की सुविधा और दूसरे खर्चों सहित ना जाने कितनी सुविधाओं का भोग यह अलगाववादी नेता करते आए हैं। मजे की बात यह है कि यह नेता देश के खर्चे पर एक और लक्जरियस जिंदगी जी रहे हैं, ऊंचा काम धंधा कर रहे हैं, अपने बच्चों और परिजनों को अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं वहीं कश्मीर के आम नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद करते हुए देश में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं।

देश के साथ नमक हरामी करते हुए पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं। जो सेना देश की रक्षा और कश्मीर में जनजीवन पर आने वाले हर संकट में कश्मीरियों के साथ खड़ी है उसी के खिलाफ पत्थरबाजी, नारेबाजी, दुर्व्यवहार और ना जाने कैसे कैसे राष्ट्र विरोधी कार्यों के लिए उकसाने में कमी नहीं छोड़ रहे। यहां तक कि घुसपैठियों और आतंकवादियों के रक्षा कवच के रूप में काम कर रहे हैं।

दरअसल पुलवामा की घटना के बाद जिस तरह से देश में जनाक्रोश सामने आया है यह अपने आप में समूचे देश की जनभावनाओं को प्रदर्शित करता है। देश का क्या कोई सा भी कोना हो, क्या युवा, क्या वृद्ध अपितु बच्चे भी जिस तरह से आक्रोशित और उद्वेलित हो रहे हैं वह वास्तव में राष्ट्र भक्ति का ज्वार है और यह साफ हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान के पक्ष में या जाने अनजाने या यों कहें कि जानीमानी रणनीति के तहत आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होने वालों के लिए भी यह सबक है। दुर्भाग्य यह है कि देश में ही अपने आप पर खतरा बताने वाले व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आए दिन सरकारी सम्मान की वापसी की हुंकार भरने वाले ना जाने किस कोने में छिप गए हैं। आखिर देश की रक्षा में रात दिन जान जोखिम में डालकर सीमाओं पर तैनात वो भी पेरा मिलिट्री फोर्स तक के जवानों के प्रति भी देश का कोई दायित्व होता है। भाषण देना, आरोप लगाना, मानवाधिकारों की बात करना, आलोचना करना बहुत आसान है।

मीडिया के सामने गाल बजाकर सुर्खियों में आना एक बात है पर कभी बेगुनाह सिपाहियों या यों कहें कि सैनिकों के पक्ष में आवाज उठाने का इन लोगों ने प्रयास किया है। बल्कि देखा जाए तो इस तरह के छद्म एजेण्डा पर काम करने वाले लोगों के खिलाफ भी अब समय आ गया है जब देशवासियों को आवाज उठानी होगी।

विचारणीय है कि जो अलगाववादी नेता हैं या जो पाकिस्तानपरस्त हैं या जो घाटी में देशविरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और जो अपने आप को कश्मीरियों का खैरख्वाह मानते हैं उन्हें सुरक्षा मांगने की क्या जरूरत है भई। वे तो कश्मीर में रह रहे हैं, उनके फॉलोवर हैं, देश विरोधी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, पाकिस्तान सहित विदेशों से पैसा ले रहे हैं फिर देश से सुरक्षा व अन्य सुविधाएं क्यों पाना चाहते हैं ? प्रश्न यही नहीं रुकता, सवाल यह भी उठता है कि इन्हें अपनी जिंदगी को किससे खतरा है।

एक अलगाववादी नेता जो सीधे सीधे देशविरोधी गतिविधियों में लिप्त है मजे की बात यह कि सरकार उसे इस तरह की गतिविधियों के संचालन और नेतृत्व करने का अवसर देते हुए यहां तक कि एक दो नहीं 20 से 25 तक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करा रही है। जिस थाली में खाएं उसी में छेद करने वाले इन अलगाववादियों को आखिर यह सुविधा क्यों ? यही कारण है कि सरकार द्वारा इन नेताओं की सुरक्षा और सुविधाओं को छिनने की घोषणा का समूचे देश ने स्वागत किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सेना को खुली छूट देने और जहां चाहे व जैसे चाहे कार्यवाही करने की छूट के साथ ही सेना द्वारा देश के खिलाफ बंदूक उठाने वालों को खुली चेतावनी देते हुए समर्पण करने या गोली में से एक चुनने का अवसर देकर साफ कर दिया है कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि अब समर्पण नहीं देश विरोधी और सेना के विरोध में गतिविधियां करने वालों खासतौर से आतंकवादियों को संरक्षण देने या पत्थरबाजी करने वालों का जवाब अब गोली ही होनी चाहिए इससे नीचे किसी तरह की रियायत स्वीकार नहीं। आखिर सैनिक, सिपाही और सुरक्षा बलों के जवान कब तक अपनी कुर्बानी देते रहेंगे। देश चाहता है अब सरकार और सेना ऐसा कदम उठाए जिससे पाकिस्तान और अलगाववाद दोनों की कमर तोड़ी जा सके। इनके पक्ष में आवाज उठाने वालों को भी देशद्रोही से कम नहीं माना जाना चाहिए यही आज समूचे देश की आवाज है।